revenue due to export of old and used rig under the free shipping bill.

(c) Matter has been referred to Central Vigilance Commission for their advice.

बैंको में नान-परफोरमिंग एसेट्स की प्रतिशतता

1662. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री 3 दिसम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 1202 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नान-परफोरमिंग एसेट्स लगभग 17 प्रतिशत तक है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) उनके कुल अग्रिमों का 17.12 प्रतिशत थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार 24.78 प्रतिशत और दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार 19.45 प्रतिशत थी।

Proposal for Changes in Public Trust Act

1663. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government propose to make changes in the Public Trust Act to control or regularise their deposits specially about the selection of banks by PSUs and Semi-Government Institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): No, Sir. Govemment does not propose to make changes in the Indian Trusts Act, 1882.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अतंर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता

1664. **श्रीमती मालती शर्मा :**
श्री राजनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पालीभीत में इस योजना का दुरूपयोग किया जा रहा है एंव सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद बैंक अधिकारी कमीशन की मांग करते हैं जिससे बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पडता है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) क्या नैनीताल बैंक, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) के प्रबंधकों द्वारा भी कमीशन की मांग की जाती है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अतंर्गत उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा मंजूर और संवितरित ऋणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-